

संशोधित अनुमान 2014-2015

वर्ष 2014-15 का संशोधित अनुमान बजट अनुमानों में ₹ 113,734 करोड़ की निवल गिरावट को दर्शाता है। आयोजना-भिन्न व्यय में ₹ 6,668 करोड़ की वृद्धि देखी गई है और आयोजना व्यय में ₹ 107,066 करोड़ की गिरावट हुई है। अन्तर की विविध प्रमुख मदों को नीचे दर्शाया जा रहा है:-

(करोड़ रुपए)

	बजट 2014-15	संशोधित 2014-15	घट-बढ़ बचत(-)/ आधिक्य(+)
आयोजना-भिन्न			
1. राज्य सरकारों को अनुदान	69084	79166	(+)10082
2. खाद्य सब्सिडी	115000	122676	(+) 7676
3. पुलिस	46390	48112	(+) 1722
4. ब्याज भुगतान तथा ऋण चुकाना	427011	411354	(-)15657
5. रक्षा	229000	222370	(-) 6630
6. पेट्रोलियम सब्सिडी	63427	60270	(-) 3157
7. पूंजी परिव्यय (रक्षा को छोड़कर)	10039	7771	(-) 2268
8. उर्वरक सब्सिडी	72970	70967	(-) 2003
9. डाक घाटा	6908	6378	(-) 530
10. पेंशन	81983	81705	(-) 278
11. अन्य आयोजना भिन्न व्यय	98080	102455	(+) 4375
जोड़ (आयोजना-भिन्न) व्यय	1219892	1213224	(-) 6668
आयोजना			
1 केन्द्रीय आयोजना	236592	189766	(-)46826
2 राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	338408	278168	(-)60240
जोड़ आयोजना व्यय	575000	467934	(-)107066
कुल व्यय			
(आयोजना + आयोजना-भिन्न)	1794892	1681158	(-)113734

आयोजना-भिन्न

- मुख्यतः सीएमटी फेजिंग आउट में राजस्व हानि के लिए राज्यों को दिए गए प्रतिपूर्ति भुगतान के प्रावधान के कारण रही।
- वृद्धि मुख्यतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधि. के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त प्रावधानों के कारण रही।
- वृद्धि, आंतरिक सुरक्षा पर उच्चतर अपेक्षाओं के कारण रही।
- कमतर अपेक्षा बाजार ऋणों, नकद प्रबन्धन बिलों, राजकोषीय हुन्डियों, राजस्व निधियों तथा अन्य अनिवार्यताओं पर ब्याज के भुगतान के कारण रही।
- कमी मुख्यतः रक्षा सेवाओं के अन्तर्गत कमतर पूंजी व्यय अपेक्षाओं के कारण हुई।

- घटोत्तरी मुख्यतः पोस्ट एपीएम सब्सिडियों के जारी न रहने के कारण रही।
- घटोत्तरी मुख्यतः सीमा सड़क संगठन, तटरक्षक संगठन द्वारा और कार्यालय भवनों के निर्माण पर कमतर अपेक्षाओं के कारण रही।
- विनियंत्रित उर्वरकों को रियायत के साथ किसानों को बेचने में वर्ष व्यय मांग के कारण।
- घटोत्तरी पोस्टल घाटे में राष्ट्रीय बचत प्रहस्तन के लिए प्रभारित एजेंसी को बढ़े हुए भुगतान के कारण हुई।
- रक्षा पेंशनों के अन्तर्गत कम जरूरतों के कारण मामूली घटोत्तरी रही।

योजना

- घटोत्तरी मुख्यतः कृषि और सहकारिता, कृषि अनुसंधान और शिक्षा, पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन, परमाणु, ऊर्जा, आयुष, फार्मास्यूटिकल, नागर विमानन, दूरसंचार, डाक, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, संस्कृति, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग, पेयजल और स्वच्छता, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन, विदेश, आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, एड्स नियंत्रण, भारी उद्योग, गृह मंत्रालय, आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता, उच्च शिक्षा, सूचना एवं प्रसारण, श्रम और रोजगार, विधि और न्याय, सूक्ष्म लघु तथा माध्यम उद्यम, खान, अल्पसंख्यक मामले, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, योजना, विद्युत, सड़क परिवहन और राजमार्ग, ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, बायोटेक्नोलोजी, शिपिंग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अंतरिक्ष, कपड़ा, पर्यटन, जनजातीय कार्य, शहरी विकास, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा निर्मलीकरण, महिला एवं बाल विकास तथा युवा मामले और खेल आदि के परिव्यय में कमी के कारण हुई।
- घटोत्तरी कृषि और सहकारिता, पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन, आयुष, वाणिज्य, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन, आर्थिक कार्य, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, गृह मंत्रालय, आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता, उच्च शिक्षा, श्रम और रोजगार, अल्पसंख्यक मामले, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, भू-संसाधन, कपड़ा, जनजातीय कार्य, शहरी विकास, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा निर्मलीकरण, महिला एवं बाल विकास तथा युवा मामले और खेल के केंद्रीयकृत प्रावधानों और संघ शासित योजनाओं में घटे हुए परिव्यय के कारण रही।